

## झारखंड सरकार ने कृषि ऋण माफ किया

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड सरकार ने 400.66 करोड़ रुपए के [कृषि ऋण माफ](#) करने की घोषणा की है।

- 1,76,977 किसानों को लाभान्वित करने वाला यह नरिणय 26 सतिंबर, 2024 को [प्रत्यक्ष लाभ अंतरण \(Direct Benefit Transfer-DBT\)](#) के माध्यम से लागू किया गया था।

### मुख्य बढि

- किसानों की चुनौतियों को संबोधति करना:
  - ऋण माफी का उद्देश्य प्रतिकिसान 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ करके ऋण के बोझ को कम करना है।
  - यह माफी झारखंड के किसानों द्वारा अनुभव की जा रही गंभीर कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए की गई है, जहाँ 80% आबादी अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर है।
- आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक कृषि को बढावा देना:
  - सरकार ने किसानों से बदलती जलवायु से निपटने के लिये पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ वैकल्पिक कृषि तकनीक अपनाने का आग्रह किया।
  - झारखंड सरकार ने राज्य के विकास के लिये आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल दिया, भले ही झारखंड खनिज और वन संसाधनों से समृद्ध है।

### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना

- उद्देश्य: इसे लाभार्थियों तक सूचना और धन के सरल/तेज प्रवाह के लिये तथा वतिरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये एक सहायता के रूप में देखा गया है।
- कार्यान्वयन: यह भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया एक मशिन या पहल है, जो सर्वजनिक वतिरण प्रणाली में सुधार लाने के लिये है।
  - महालेखा नयित्त्रक कार्यालय की [सार्वजनिक वतितीय प्रबंधन प्रणाली \(Public Financial Management System-PFMS\)](#) के पुराने संस्करण, [केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली \(Central Plan Scheme Monitoring System-CPSMS\)](#) को [प्रत्यक्ष लाभ अंतरण](#) के लिये साझा प्लेटफार्म के रूप में कार्य करने के लिये चुना गया था।
- DBT के घटक: DBT योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिक घटकों में [लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली](#), [भारतीय रिज़र्व बैंक \(RBI\)](#), [भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम \(NPCI\)](#), [सार्वजनिक और निजी कषेत्र के बैंक](#), [कषेत्रीय ग्रामीण बैंक](#) और [सहकारी बैंक](#) (बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपिटान प्रणाली, NPCI का आधार भुगतान ब्रजि) आदि के साथ एकीकृत एक मज़बूत भुगतान और सुलह मंच शामिल है।